ग्रेटर नोएडा बनेगा सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का गढ़

लखनऊ। सेमी कंडक्टर की बड़ी कंपनियों को लाने के लिए तैयार 'सेमी कंडक्टर पालिसी' को जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके जरिए दिग्गज कंपनियों को ऐसे प्रस्ताव देने की तैयारी है जो अब तक किसी देश में किसी राज्य ने न दिए हों। वर्तमान में सेमी कंडक्टर पालिसी केवल गुजरात और उड़ीसा ने तैयार की है। यूपी इसे लागू करने वाला तीसरा राज्य होगा। इंडस्ट्री के लिए ग्रेटर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट के नजदीकी क्षेत्रों को चुना गया है।

दुनिया की दिग्गज सेमी कंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को यूपी में निवेश के एवज में 75 फीसदी की पूंजी सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके अलावा स्टांप ड्यूटी में सौ फीसदी छूट, जमीन पर 80 फीसदी व बिजली बिल में 100 फीसदी तक सब्सिडी का प्रावधान है। सबसे महत्वपूर्ण पूंजी यानी कैपिटल सब्सिडी है। सेमी कंडक्टर चिप बनाने में अभी ताइवान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया का दबदबा है। दुनियाभर में इस्तेमाल होने वाली कुल चिप का 60 फीसदी अकेले ताइवान बनाता है। ब्यूरो

20 हजार करोड़ की होगी एक इकाई, छोटी इकाइयां भी 200 करोड़ की

सहायक कंपनियां होंगी स्वदेशी

सेमी कंडक्टर चिप बनाने वाली एक इकाई में न्यूनतम 20 हजार करोड़ का निवेश होगा। एक इकाई के साथ कम से कम 1800 सहायक इकाइयों की स्थापना होगी। इनकी हैसियत भी 200 करोड़ से कम नहीं होगी। ये सहायक इकाइयां स्वदेशी होंगी। यही वजह है कि बड़ी कंपनी को लाने के लिए पालिसी में 75 फीसदी यानी 15 हजार करोड़ (20 हजार करोड़ के निवेश पर) की कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है। सेमीकंडक्टर चिप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जीवन रेखा होती है। इसका कारों से लेकर स्मार्टफोन तक में इस्तेमाल होता है। भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 2026 तक 80 अरब डॉलर और 2030 तक 110 अरब डॉलर पार कर जाएगा। वर्ष 2022 में भारतीय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 27 अरब डॉलर की थी।